



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2009/ज्येष्ठ 8, 1931
No. 86] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2009/JYAISTHA 8, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

सं. एल-7/105(121)/2007-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम नोडल अभिकरण द्वारा 15-6-2009 को या इसके पश्चात् प्राप्त अल्पकालिक खुली पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन को लागू होंगे।

2. विनियम 2 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "द्विपक्षीय संव्यवहार" से मास के दौरान किसी समय अवधि के लिए ऊर्जा की नियत या परिवर्ती मात्रा के लिए व्यादेश के विनिर्दिष्ट बिन्दु से निकासी के विनिर्दिष्ट बिन्दु तक विनिर्दिष्ट क्रेता और विनिर्दिष्ट विक्रेता के बीच प्रत्यक्षतः या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से या अनाम बोली के माध्यम से पावर एक्सचेंज पर प्राप्त ऊर्जा के विनियम के लिए संव्यवहार अभिप्रेत हैं।'

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(च) "विस्तृत प्रक्रिया" से विनियम 4 के अधीन जारी प्रक्रिया अभिप्रेत है।'

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘ (झ) “दीर्घ-कालिक ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच अनुदत्त की गई है ।’

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (झ) के पश्चात् खंड (झक) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘ (झ-क) “मध्य-कालिक ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए मध्य-कालिक पहुंच प्रदत्त की गई है ।’

(5) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ठ) का लोप किया जाएगा ।

(6) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘ (ढक) “अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच” से एक समय पर एक मास तक की अवधि के लिए निर्बाध पहुंच अभिप्रेत है ।’

(7) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के नए अंतःस्थापित उपखंड (ढक) के पश्चात्, खंड (ढख) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(ढख) “अल्प-कालिक ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त कर ली है या प्राप्त करने के लिए आशयित है ।’

3. “निर्बाध पहुंच” और “निर्बाध पहुंच ग्राहक” पदों का अंतःस्थापन

“निर्बाध पहुंच” तथा “निर्बाध पहुंच ग्राहक” पद, जहां-जहां मूल विनियम में आते हैं, के स्थान पर क्रमशः “अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच” तथा “अल्प-कालिक ग्राहक” पद रखे जाएंगे ।

4. **विनियम 3 का संशोधन** - मूल विनियम के विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“विस्तार

“3 (1) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए अल्प-कालिक ग्राहक के बजाय दीर्घ-कालिक ग्राहक तथा मध्य-कालिक ग्राहक को पूर्विकता दी जाएगी ।

(2) अल्प-कालिक ग्राहक निम्नलिखित के आधार पर दीर्घ-कालिक ग्राहक तथा मध्य-कालिक ग्राहक द्वारा उपयोग के पश्चात् अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर उपलब्ध अधिशेष क्षमता पर अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए पात्र होंगे -

(क) अंतर्निहित डिजाइन मार्जिन,

(ख) विद्युत प्रवाह में फेरफार के कारण उपलब्ध मार्जिन ; और

(ग) भावी भार वृद्धि या उत्पादन वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए सृजित इन-बिल्ट अतिरिक्त पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन ।”

5. **विनियम 4 का संशोधन** - मूल विनियम के विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ विस्तृत प्रक्रिया

4. इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, जब तक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र उसके द्वारा प्रचालित करने तक तथा तत्पश्चात् सरकारी कंपनी या अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकरण या निगम, आयोग का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् निर्बाध पहुंच को प्रचालन करने के लिए तथा इन विनियमों के अधीन सम्मिलित न किए गए किसी अवशिष्ट मामले के लिए विस्तृत प्रक्रिया जारी करेगी ।”

6. **विनियम 8 का संशोधन** - (1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3)(क) सहमति या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी अभिप्राप्त करने के लिए, आवेदन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समक्ष किया जाएगा, जो आवेदन की प्राप्ति के समय से चौबीस घंटे के भीतर ई-मेल या फैक्स, या संचार की प्राथिक रूप से मान्य पद्धति द्वारा आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा :

परंतु जहां आवेदन व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाता है तो आवेदन देने के समय पर अभिस्वीकृति दी जाएगी ।

(ख) यथास्थिति, सहमति या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी के लिए आवेदन पर कार्यवाही करते समय, राज्य भार प्रेषण केन्द्र निम्नलिखित को सत्यापित करेगा, अर्थात् :-

(i) प्रवृत्त ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार समय-ब्लॉक-वार ऊर्जा मीटरिंग तथा लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना ; तथा

(ii) राज्य नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता ।

(ग) जहां आवश्यक अवसंरचना तथा राज्य नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धि सुस्थापित हो जाती है वहां राज्य भार प्रेषण केन्द्र आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के तीन कार्यदिवस के भीतर संचार की कोई मान्य प्राथिक पद्धति के अतिरिक्त, ई-मेल या फैक्स द्वारा, यथास्थिति, अपनी सहमति या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी के बारे में बताएगा :

परंतु यह कि जब किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन किया गया हो, तब राज्य भार प्रेषण केन्द्र आवेदन की प्राप्ति के सात कार्यदिवस के भीतर आवेदक को संचार की कोई मान्य प्राथिक पद्धति के अतिरिक्त, ई-मेल या फैक्स द्वारा ऐसी सहमति या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी के बारे में बताएगा ।

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (3क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3क) यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह पाता है कि, यथास्थिति, सहमति या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी के लिए आवेदन किसी भी प्रकार से अधूरा है या त्रुटियुक्त है तो वह आवेदन

की प्राप्ति के दो कार्यदिवस के भीतर संचार की कोई अन्य प्रायिक मान्य पद्धति के अलावा, ई-मेल या फ़ैक्स के माध्यम से आवेदन को कमियों या त्रुटि के बारे में बताएगा :

परंतु यह कि ऐसे मामलों में, जहां राज्य भार प्रेषण केन्द्र ने आवेदन में किसी कमी या त्रुटि के बारे में बता दिया हो, आवेदन प्राप्त करने की तारीख वह होगी जिस तारीख को यथास्थिति, कमियों तथा त्रुटियों को दूर करने के पश्चात् आवेदन सम्यक् रूप से प्राप्त होता है ।”

(3) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ (4) यदि आवेदन ठीक पाया गया हो किन्तु राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य नेटवर्क में आवश्यक अवसंरचना या अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता न होने के आधार पर, यथास्थिति, सहमति या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी देने से इंकार कर देता है तो ऐसी इंकारी की सूचना देने से इंकार करने के कारणों के साथ खंड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, यथास्थिति, तीन कार्य दिवस या सात कार्यदिवस के भीतर संचार की किसी अन्य प्रायिक रूप से मान्य पद्धति के अतिरिक्त, ई-मेल या फ़ैक्स द्वारा आवेदक को ऐसे इंकार के बारे में संसूचित करेगा :

परंतु यह कि यदि जहां राज्य भार प्रेषण केन्द्र ने आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, यथालागू तीन कार्य दिवस या सात कार्यदिवस की विनिर्दिष्ट की अवधि के भीतर, यथास्थिति, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो दिन के भीतर आवेदक में किसी कमी या त्रुटि या इंकार या सहमति या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी के बारे में संसूचित नहीं किया हो तो, यथास्थिति, सहमति या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी प्रदत्त समझी जाएगी :

परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदत्त की गई समझी गई है वहां आवेदक, विनियम 9 के खंड (1) के अधीन आवेदन करते समय निम्नलिखित घोषणा करने वाला एक शपथपत्र, (विस्तृत प्रक्रिया में दिए गए प्ररूप में) जो नोटरीकृत होगा, नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करेगा,-

(क) कि राज्य भार प्रेषण केंद्र, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, यथास्थिति, आवेदन में पाई गई किसी कमी या त्रुटि या उसके इन्कार करने के कारण या सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी को बताने में असफल हो गया है ;

(ख) प्रवृत्त ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार समय-ब्लॉक-वार ऊर्जा मीटरिंग तथा लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना विद्यमान है तथा शपथपत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करेगा —

- (i) कमी को दूर करने या त्रुटियों को सुधारने, यदि संसूचित किया गया हो, के पश्चात्, यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी चाहने के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र को किए गए आवेदन की पूर्ण प्रति ; और
- (ii) राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई अभिस्वीकृति, यदि कोई हो, की प्रति, या राज्य भार प्रेषण केंद्र को आवेदन भेजने का कोई अन्य साक्ष्य ।”

7. विनियम 13 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“आकस्मिकता में संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया

13. आकस्मिकता की दशा में, पूर्ववर्ती दिन के 1500 घंटे के कट-आफ समय के पश्चात् भी अल्प-कालिक आकस्मिकता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्रेता या उसकी ओर से, व्यापारी ऊर्जा के स्रोत का पता लगाएगा और पावर एक्सचेंज पता लगाने के लिए अपने प्लेटफार्म का प्रस्ताव कर सकेगा तथा वे अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए नोडल अभिकरण को आवेदन करेंगे और इस दशा में, नोडल अभिकरण विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार यथाशीघ्र तथा यथासाध्य सीमा तक अनुरोध को पूरा करने का प्रयास करेगा ।”

8. विनियम 14 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“अनुसूची का पुनरीक्षण

14. (1) अग्रिम में नोडल अभिकरण द्वारा स्वीकृत या पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच अनुसूचियों को रद्द किया जा सकेगा या कि अल्प-कालिक ग्राहक द्वारा नोडल अभिकरण के किए गए इस आशय के आवेदन को पुनरीक्षित करेगा :

परंतु यह कि अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच अनुसूचियों के ऐसे रद्दकरण या पुनरीक्षण करने तक के दो दिन की न्यूनतम अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रभावी नहीं होगा :

परंतु यह और कि उस दिन जिसको अनुसूची के रद्दकरण या पुनरीक्षण करने तक की सूचना की तामील नोडल अभिकरण को की जाती है तथा उस दिन जिससे ऐसा रद्दकरण या पुनरीक्षण कार्यान्वित किया जाता है, को दो दिन की अवधि की संगणना के लिए अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच को रद्द या उसका पुनरीक्षण चाहने वाला व्यक्ति नोडल अभिकरण द्वारा मूलतः अनुमोदित अनुसूची के अनुसार उस अवधि, जिसके लिए, यथास्थिति, अनुसूची के रद्दकरण या उसका पुनरीक्षण चाहा गया है, के पहले दो दिन के लिए पारेषण प्रभारों का संदाय करेगा तथा तत्पश्चात् ऐसे रद्दकरण या पुनरीक्षण की अवधि के दौरान नोडल अभिकरण द्वारा तैयार पुनरीक्षित अनुसूची के अनुसार संदाय करेगा ।

(3) रद्दकरण की दशा में, विनियम 17 के अधीन विनिर्दिष्ट, प्रचालन प्रभार दो दिन के लिए या दिन में रद्दकरण की अवधि जो भी कम हो, के लिए संदेय होंगे ।

टिप्पण : इस विनियम के उपबंध उन अल्प-कालिक ग्राहकों को भी लागू होंगे जिन्हें 15.6.2009 के पूर्व अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदत्त की गई हो ।”

9. **विनियम 15 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र किसी संव्यवहार को रद्द करके या पुनः अनुसूचीकरण करके किसी भी पारेषण करीडोर पर ऊर्जा प्रवाह में कटौती कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे किसी

संव्यवहार के रद्दकरण या कटौती से कारीडोर पर पारेषण निरोध कम होने की संभावना हो या ग्रिड में सुधार की संभावना हो :

परंतु यह कि ग्रिड संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संव्यवहार को रद्द करने या उसमें कटौती करते समय, अल्प-कालिक, मध्य-कालिक, तथा दीर्घ-कालिक संव्यवहारों के बीच सबसे पहले अल्प-कालिक संव्यवहारों को रद्द या उनमें कटौती की जाएगी उसके बाद मध्य-कालिक में तथा तत्पश्चात् दीर्घ-कालिक संव्यवहारों को रद्द या उनमें कटौती की जाएगी :

परंतु यह और कि किसी अल्प-कालिक संव्यवहार को रद्द करने या कटौती करते समय सबसे पहले द्विपक्षीय संव्यवहारों को रद्द या उनमें कटौती की जाएगी तथा उसके पश्चात् सामूहिक संव्यवहारों को रद्द या उनमें कटौती की जाएगी ।”

10. विनियम 16 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पारेषण प्रभार

16.(1) द्विपक्षीय संव्यवहारों की दशा में, अंतःक्षेपण के स्थान या स्थानों पर पारेषण के लिए अनुमोदित ऊर्जा के लिए अल्प-कालिक ग्राहक के लिए नीचे विनिर्दिष्ट दर पर पारेषण प्रभार संदेय होंगे :

संव्यवहार का प्रकार	पारेषण प्रभार (कुल) (रु. मेगावाट घंटों में)
(क) द्विपक्षीय, अंतर-राज्यिक	80
(ख) द्विपक्षीय, समीपवर्ती क्षेत्रों के बीच	160
(ग) द्विपक्षीय, एक या उससे अधिक मध्यवर्ती क्षेत्रों के माध्यम से चक्रण	240

(2) सामूहिक संव्यवहार की दशा में, अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान पर निकासी के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रूप से पारेषण हेतु अनुमोदित ऊर्जा के लिए 100 मेगावाट की दर पर पारेषण प्रभार संदेय होंगे ।

(3) अंतःराज्यिक इकाईयां खंड (1) या (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रभारों के अतिरिक्त राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए, अपने-अपने राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित पारेषण प्रभारों का अतिरिक्त रूप से संदाय करेंगे :

परंतु यह कि यदि राज्य आयोग ने पारेषण प्रभार अवधारित नहीं किए हैं तो अपने-अपने राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषित ऊर्जा हेतु प्रभार 80 मेगावाट घंटे की दर पर संदेय होंगे :

परंतु यह कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए राज्य आयोग द्वारा पारेषण प्रभारों का नियतन किया जाना निर्बाध पहुंच इंकार करने का आधार नहीं माना जाएगा :

परंतु यह और कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए संदेय पारेषण प्रभार के बारे में संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को बताया जाएगा जो कि इन दरों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे :

परंतु यह भी कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए संदेय पारेषण प्रभारों को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा ।”

11. विनियम 20 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 20 के खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (6) इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रभारों से भिन्न, कोई भी प्रभार, ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होंगे जिसे इन विनियमों के अधीन अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच अनुदत्त की हो ।”

12. विनियम 25 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

2040 64/09-2

“पारेषण प्रभारों तथा प्रचालन प्रभारों का संग्रहण तथा संवितरण

25. (1) निर्बाध पहुंच अनुज्ञात किए गए व्यक्तियों द्वारा संदेय पारेषण प्रभार तथा प्रचालन प्रभार सामूहिक संव्यवहार की दशा में, राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभारों के सिवाय नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत और संवितरित किए जाएंगे।

(2) राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए नोडल अभिकरण द्वारा एकत्रित पारेषण प्रभारों का संवितरण केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को ऐसे पारेषण प्रभारों का 25% संवितरण करने के पश्चात् निम्नलिखित रीति से प्रत्यक्षतः किया जाएगा :-

(क) अंतःप्रादेशिक द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में : संबंधित क्षेत्र को पारेषण प्रभारों का 75%

(ख) समीपवर्ती प्रदेशों के बीच द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में : प्रत्येक प्रदेश के लिए पारेषण प्रभारों का 37.5% ; और

(ग) एक या अधिक मध्यस्थ प्रदेशों के माध्यम से द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में : प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक आयात और निर्यात के लिए पारेषण प्रभारों का 25% तथा सभी मध्यस्थ प्रदेशों के बीच समान रूप से आबंटित किए जाने वाले पारेषण प्रभारों का शेष 25%।

(3) अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या निकासी के प्रत्येक स्थान के लिए सामूहिक संव्यवहार के लिए राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए संगृहीत पारेषण प्रभार निम्नलिखित रीति से नोडल अभिकरण द्वारा संवितरित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता : 25%

(ख) यथास्थिति, अंतःक्षेपण या प्राप्त करने के स्थान के लिए क्षेत्र के दीर्घ-कालिक ग्राहक : 75%

(4) पारेषण प्रभारों का संवितरण दीर्घ-कालिक ग्राहकों को उनके द्वारा संदेय मासिक पारेषण प्रभारों के अनुपात में किया जाएगा ।

(5) राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों को संबंधित राज्य पारेषण उपयोगिता को संवितरित किया जाएगा ।

(6) यदि अल्प-कालिक ग्राहक अंतःराज्यिक इकाई है तो नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत किए गए प्रचालन प्रभारों तथा पारेषण प्रभारों में राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे ।”

13. नए विनियम 25क का अंतस्थापन : मूल विनियम के विनियम 25 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम 25क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्रदान न की जाने वाली अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच

25क. जब आयोग द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र ऐसी इकाईयों या ऐसी इकाईयों के सहयुक्तों को अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदत्त नहीं करेगा जो लगातार तथा जानबूझकर अनुसूचित विनियम प्रभार, पारेषण प्रभार, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, संकुचन प्रभार, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के लिए फीस तथा प्रभार, जिसमें एकीकृत भार प्रेषण या संचार स्कीम के लिए प्रभार भी सम्मिलित हैं, के संदाय में व्यतिक्रम करते हैं ।”

14. विनियम 26 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्रतिषेध तंत्र

26. इन विनियमों के अधीन उद्भूत सभी विवादों का विनिश्चय आयोग द्वारा व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर किया जाएगा ।”

15. विनियम 27 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 27 के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“जानकारी प्रणाली - राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र”

19. नए विनियम 27क का अंतःस्थापन : मूल विनियम के विनियम 27 के पश्चात्, विनियम 27क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“जानकारी प्रणाली - राज्य भार प्रेषण केंद्र

27क. प्रत्येक भार प्रेषण केंद्र, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिन के भीतर, अपनी वेबसाइट को विकसित करेगा तथा “अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच संबंधी जानकारी” नामक पृथक् वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी डालेगा :

(क) उन संव्यवहारों की सूची जिसके लिए सहमति प्रदत्त की गई है तथा उन इकाईयों की सूची जिन्हें, यथास्थिति, सहमति या ‘अनापत्ति’ या पूर्व स्थायी निकासी उस मास, जिसमें ऐसी सहमति या अनापत्ति या पूर्व स्थायी निकासी प्रदत्त की गई है, की समाप्ति तक प्रदत्त की गई हो, जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित होगा :

- (i) ग्राहक का नाम ;
- (ii) यथास्थिति, सहमति या ‘अनापत्ति’ या स्थायी निकासी की अवधि (आरंभिक तारीख तथा अंतिम तारीख) ;
- (iii) अंतःक्षेपण तथा निकासी के स्थान पर ; तथा
- (iv) स्वीकृति अनुसूची (मेगावाट) ।

टिप्पण

प्रास्थिति रिपोर्ट को प्रतिदिन अद्यतन किया जाएगा ;

- (ख) ठीक पूर्ववर्ती 52 सप्ताहों के लिए राज्य नेटवर्क हेतु औसत पारेषण हानियां ;
- (ग) राज्य नेटवर्क के लिए लागू पारेषण प्रभार तथा पारेषण हानियां ;
- (घ) उन आवेदनों की सूची, जहां, यथास्थिति, सहमति या “अनापत्ति” या स्थायी निकासी अनुदत्त न की गई थी, इंकार के कारण, जिन्हें आवेदन में दी गई अनुसूचीकरण अवधि के पश्चात् एक मास तक प्रदर्शित किया जाना है ; तथा
- (ङ) विनिश्चय के लिए लंबित आवेदनों की सूची ।”

आलोक कुमार, सचिव
[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2009

No. L-7/105(121)/2007-CERC.—In exercise of powers conferred by Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as “the principal regulations”), namely :—

1. Short Title, Commencement and Application - (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Amendment) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall apply to the application for grant of short-term open access, received by nodal agency on or after 15.6.2009.

2. Amendment of regulation 2 - (1) Sub-clause (b) of clause (1) of regulation 2 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

“(b) “bilateral transaction” means a transaction for exchange of energy (MWh) between a specified buyer and a specified seller, directly or through a trading licensee or discovered at power exchange through anonymous bidding, from a specified point

of injection to a specified point of drawl for a fixed or varying quantum of power (MW) for any time period during a month; "

(2) Sub-clause (f) of clause (1) of regulation 2 of the principal regulations shall be substituted as under, namely -

"(f) "detailed procedure" means the procedure issued under regulation 4; "

(3) Sub-clause (i) of clause (1) of regulation 2 of the principal regulations shall be substituted as under, namely -

"(i) "long-term customer" means a person granted long-term access for use of the inter-State transmission system."

(4) After sub-clause (i) of clause (1) of regulation 2 of the principal regulations, clause (i-a) shall be inserted as under, namely-

"(i-a) "medium-term customer" means a person granted medium-term open access for use of the inter-State transmission system."

(5) Sub-clause (l) of clause (1) of regulation 2 of the principal regulations shall be deleted.

(6) After sub-clause (n) of clause (1) of regulation 2 of the principal regulations, clause (n-a) shall be inserted as under, namely-

"(n-a) "short-term open access" means open access for a period up to one (1) month at one time."

(7) After newly inserted sub-clause (n-a) of clause (1) of regulation 2 of the 'principal regulations, clause (n-b) shall be inserted as under, namely

"(n-b) "short-term customer" means a person who has availed or intends to avail short-term open access."

3. Substitution of Expressions "open access" and "open access customer"

- The expressions "open access" and "open access customer" wherever occurring in the principal regulations shall be substituted by the expressions "short-term open access" and short-term customer" respectively.

4. Amendment of regulation 3 - Regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as under, namely –

"Scope

"3. (1) The long-term-customer and the medium-term customer shall have priority over the short-term customer for use of the inter-State transmission system.

(2) The short-term customer shall be eligible for short-term open access over the surplus capacity available on the inter-State transmission system after use by the long-term customer and the medium-term customer, by virtue of-

(a) inherent design margins;

(b) margins available due to variation in power flows; and

(c) Margins available due to in-built spare transmission capacity created to cater to future load growth or generation addition.”

5. Amendment of regulation 4 - Regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

“Detailed Procedure

4. Subject to the provisions of these regulations, the Central Transmission Utility, till the Regional Load Despatch Centre is operated by it and thereafter the Government company or any authority or corporation notified by the Central Government under sub-section (2) of Section 27 of the Act: shall, after obtaining prior approval of the Commission, issue the detailed procedure to operationalise open access and on any residual matter not covered under these regulations.

6. Amendment of regulation 8 - (1) Clause (3) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

“(3) (a) For obtaining concurrence or ‘no objection’ or prior standing clearance an application shall be made before the State Load Despatch Centre who shall, acknowledge receipt of the application, either by e-mail or fax, or any other usually recognised mode of communication, within twenty four hours from the time of receipt of the application:

Provided that where the application has been submitted in person, the acknowledgement shall be provided at the time of submission of the application.

(b) While processing the application for concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, the State Load Despatch Centre shall verify the following, namely-

(i) existence of infrastructure necessary for time-block-wise energy metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid Code in force, and

(ii) availability of surplus transmission capacity in the State network.

(c) Where existence of necessary infrastructure and availability of surplus transmission capacity in the State network has been established, the State Load Despatch Centre shall convey its concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, to the applicant by e-mail or fax, in addition to any other usually recognised mode of communication, within three (3) working days of receipt of the application:

Provided that when short-term open access has been applied for the first time by any person, the buyer or the seller, the State Load Despatch Centre shall convey to the applicant such concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, within seven (7) working days of receipt of the application by e-mail or fax, in addition to any other usually recognised mode of communication.

- (2) After clause (3) of regulation 8 of the principal regulations as amended, clause (3A) shall be inserted as under, namely-

"(3A) In case the State Load Despatch Centre finds that the application for concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, is incomplete or defective in any respect, it shall communicate the deficiency or defect to the applicant by e-mail or fax, in addition to any other usually recognised mode of communication, within two (2) working days of receipt of the application:

Provided that in cases where the State Load Despatch Centre has communicated any deficiency or defect in the application, the date of receipt of application shall be the date on which the application has been received duly completed, after removing the deficiency or rectifying the defects, as the case may be."

- (3) Clause (4) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

"(4) In case the application has been found to be in order but the State Load Despatch Centre refuses to give concurrence or 'no objection' or prior standing clearance as the case may be, on the grounds of non-existence of necessary infrastructure or unavailability of surplus transmission capacity in the State network, such refusal shall be communicated to the applicant by e-mail or fax, in addition to any other usually recognized mode of communication, within the period of three (3) working days or

seven (7) working days, as the case may be, from the date of receipt of the application, specified under clause (3), along with reasons for such refusal:

Provided that where the State Load Despatch Centre has not communicated any deficiency or defect in the application within two (2) days from the date of receipt of application or refusal or concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, within the specified period of three (3) working days or seven (7) working days, as applicable, from the date of receipt of the application, concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, shall be deemed to have been granted:

Provided further that where concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, is deemed to have been granted by the State Load Despatch Centre, the applicant while making application under clause (1) of regulation 9 shall submit to the nodal agency an affidavit (in the format provided in the detailed procedure), duly notarised, declaring that –

(a) the State Load Despatch Centre has failed to convey any deficiency or defect in the application or its refusal or concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, within the specified time,

(b) necessary infrastructure for time-block-wise energy metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid Code in force, is in place; and enclosing with the affidavit –

(i) a copy of the complete application after removal of deficiency or rectification of defects, if any communicated, made to the State Load Despatch

Centre for seeking concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, and

(ii) a copy of the acknowledgement, if any, given by the State Load Despatch Centre, or any other evidence in support of delivery of the application to the State Load Despatch Centre."

7. Amendment of regulation 13 - Regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

"Procedure for Scheduling a Transaction in a Contingency

13. In the event of a contingency, the buyer or on its behalf, a trader may locate, and the power exchange may offer its platform to locate, a source of power to meet short-term contingency requirements even after the cut-off time of 1500 hrs of the preceding day and apply to the nodal agency for short-term open access and scheduling and in that event, the nodal agency shall endeavour to accommodate the request as soon as may be and to the extent practically feasible, in accordance with the detailed procedure.

8. Amendment of regulation 14 - Regulation 14 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

"Revision of Schedule

14. (1) The short-term open access schedules accepted by the nodal agency in advance or on first-come-first-served basis may be cancelled or revised downwards on an application to that effect made to the nodal agency by the short-term customer:

Provided that such cancellation or downward revision of the short-term open access schedules shall not be effective before expiry of a minimum period of two (2) days:

Provided further that the day on which notice for cancellation or downward revision of schedule is served on the nodal agency and the day from which such cancellation or downward revision is to be implemented, shall be excluded for computing the period of two (2) days.

(2) The person seeking cancellation or downward revision of short-term open access schedule shall pay the transmission charges for the first two (2) days of the period for which the cancellation or downward revision of schedule, as the case may be, has been sought, in accordance with the schedule originally approved by the nodal agency, and thereafter in accordance with the revised schedule prepared by the nodal agency during the period of such cancellation or downward revision.

(3) In case of cancellation, operating charges specified under regulation 17 shall be payable for two (2) days or the period of cancellation in days, whichever is less.

Note: The provisions of this regulation shall also be applicable to the short-term customers granted short-term open access prior to 15.6.2009.

9. Amendment of regulation 15 - Clause (1) of regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

“(1) The Regional Load Despatch Centre may curtail power flow on any transmission corridor by cancelling or re-scheduling any transaction, if in its opinion

cancellation or curtailment of any such transaction is likely to relieve the transmission constraint on the corridor or to improve grid security:

Provided that subject to provisions of the Grid Code, while cancellation or curtailment of any transaction, among short-term, medium-term and long-term transactions, short-term transactions shall be cancelled or curtailed first, followed by medium-term and thereafter long term-transactions:

Provided further that while cancelling or curtailing any short-term transaction, bilateral transactions shall be cancelled or curtailed first followed by collective transactions."

10. **Amendment of regulation 16** - Regulation 16 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

"Transmission Charges

16. (1) In case of bilateral transactions, the transmission charges at the rate specified hereunder shall be payable by the short-term customer for the energy approved for transmission at the point or points of injection:

<u>Type of Transaction</u>	<u>Transmission charges(Total)</u> <u>(Rs./MWh)</u>
(a) Bilateral, intra-regional	80
(b) Bilateral, between adjacent regions	160
(c) Bilateral, wheeling through one or more	

intervening regions

240

(2) In case of the collective transactions, transmission charges at the rate of Rs. 100/MWh for energy approved for transmission separately for each point of injection and for each point of drawal, shall be payable.

(3) The intra-State entities shall pay the transmission charges for use of the State network as fixed by the respective State Commission in addition to the charges specified under clauses (1) and (2):

Provided that in case the State Commission has not determined the transmission charges, the charges for use of respective State network shall be payable at the rate of Rs.80/MWh for the electricity transmitted:

Provided further that non-fixation of the transmission charges by the State Commission for use of the State network shall not be a ground for refusal of open access:

Provided also that the transmission charges payable for use of the State network shall be conveyed to the Regional Load Despatch Centre concerned who shall display these rates on its web site:

Provided also that the transmission charges payable for use of the State network shall not be revised retrospectively."

11. Amendment of regulation 20 - Clause (6) of regulation 20 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

"(6) No charges, other than those specified under these regulations shall be payable by any person granted short-term open access under these regulations."

12. Amendment of regulation 25 - Regulation 25 of the principal regulations shall be substituted as under, namely -

"Collection and Disbursement of Transmission Charges and Operating Charges

25. (1) The transmission charges and the operating charges payable by the persons allowed short-term open access shall be collected and disbursed by the nodal agency, except for transmission charges for State network and operating charges for State Load Despatch Centre in the case of the collective transaction.

(2) The transmission charges collected by the nodal agency for use of the transmission system other than State network, for a bilateral transaction shall be directly disbursed to the long-term customers after disbursing 25% of such transmission charges to the Central Transmission Utility in the following manner -

(a) In case of intra-regional bilateral transaction: 75% of the transmission charges to the region concerned.

(b) In case of bilateral transaction between adjacent regions: 37.5% of the transmission charges for each region.

(c) In case of bilateral transaction through one or more intervening regions: 25% of the transmission charges for each of importing and

exporting each region and remaining 25% of the transmission charges to be allocated equally among all intervening regions.

(3) The transmission charges collected for use of the transmission system other than State network for a collective transaction for each point of injection and each point of drawal shall be disbursed by the nodal agency in the following manner, namely-

(a) Central Transmission Utility: 25%

(b) Long-term customers of the region of point of injection or drawal, as the case may be, is situate: 75%

(4) The transmission charges shall be disbursed to the long-term customers in proportion to the monthly transmission charges payable by them.

(5) The transmission charges for use of State network shall be disbursed to the State Transmission Utility concerned.

(6) In case an intra-State entity is the short-term customer, the operating charges and the transmission charges collected by the nodal agency shall not include the charges for use of the State network and operating charges for the State Load Despatch Centre."

13. Insertion of new regulation 25A - After regulation 25 of the principal regulations, regulation 25A shall be inserted as under, namely-

"Short-term Open Access Not To Be Granted"

25A. When so directed by the Commission, the National Load Despatch Centre or the Regional Load Despatch Centre, as the case may be, shall not grant short-term open access to the entities and associates of such entities, who consistently and willfully default in payment of Unscheduled Interchange charges, transmission charges, reactive energy charges, congestion charges and fee and charges for National Load Despatch Centre or Regional Load Despatch Centre including the charges for the Unified Load Despatch and Communication Scheme ."

14. **Amendment of regulation 26** - Regulation 26 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

"Redressal Mechanism"

26. All disputes arising under these regulations shall be decided by the Commission based on an application made by the person aggrieved."

15. **Amendment of regulation 27** - Title of regulation 27 of the principal regulations shall be substituted as under, namely-

"Information System – National Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centres"

19 **Insertion of new regulation 27A** After regulation 27 of the principal regulations, regulation 27A shall be inserted as under, namely-

"Information System – State Load Despatch Centres"

27A. Each State Load Despatch Centre, shall within 60 days of coming into force of these regulations, develop its website and post the following information on separate web-page titled "information on Inter-State Open Access":

- (a) List of bilateral transactions for which concurrence has been granted and list of entities to whom concurrence or "no objection" or prior standing clearance, as the case may be, has been granted till the end of the month in which such concurrence or no objection or prior standing clearance has been granted, indicating:
- (i) Name of customer;
 - (ii) *Period of concurrence* or "no objection" or standing clearance, as the case may be, (start date and end date);
 - (iii) Point or points of injection and drawal,; and
 - (iv) Accepted schedule (MW).

Note

The status report shall be updated daily.

- (b) Average transmission losses for the State network for the immediately preceding 52 weeks;
- (c) Applicable transmission charges and transmission losses for the State network;
- (d) List of applications where concurrence or "no objection" or standing clearance, as the case may be, was not granted, along with reasons for refusal, to be displayed till one month after the scheduling period given in the application; and
- (e) A list of applications pending for decision."

ALOK KUMAR, Secy.
[ADVT III/4/150/09-Exty.]